



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

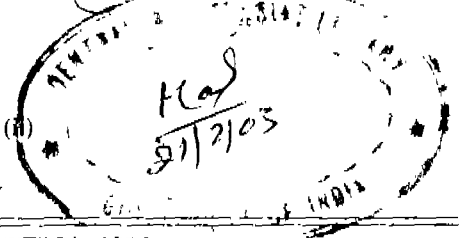
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 805]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2002/भाद्र 20, 1924

No. 805]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2002/BHADRA 20, 1924

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2002

का.आ. 988(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आयंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आयंटन) (दो मी चौंसठवां संशोधन) नियम, 2002 है।
- (2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आयंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,—

(क) “रेल मंत्रालय” शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“2. गैर सरकारी रेलें—जहाँ तक वे विषय जहाँ तक उनके लिए रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) में या सरकार और इन रेलों के बीच संविदाओं में या किन्हीं अन्य कानूनी अधिनियमितियों में, अर्थात् सुरक्षा, अधिकतम और न्यूनतम दरों और भाड़ा आदि से संबंधित विनियमों में, यह उपबंध किया गया है कि उनका नियंत्रण रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) करेगा, उस कार्य-मद को छोड़कर, जो शहरी विकास विभाग को आवंटित की गई है।”;

(ख) “शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “क. शहरी विकास विभाग” उपशीर्षक के नीचे,

(i) प्रविष्टि 13 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“13. रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड को आवंटित कार्य-मदों के अधीन रहते हुए रेल आधारित प्रणालियों की तकनीकी योजना सहित शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना और समन्वय।”;

(ii) इस प्रकार रखी गई प्रविष्टि 13 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“13क. भारतीय रेल द्वारा निर्धारित प्रणालियों को छोड़कर, रेल आधारित शहरी परिवहन प्रणालियों के लिए अधिकतम और न्यूनतम दरों तथा भाड़ों का नियतन।”।

आ. प. जै. अब्दुल कलाम

राष्ट्रपति।

[फा. सं. 1/22/1/2002—मंत्रि.]

पि. गोपालाकृष्णन, निदेशक (मंत्रिमंडल)

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th September, 2002

S. O. 988(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and sixty-fourth Amendment) Rules, 2002.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(A) under the heading “MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)”, for entry 2, the following entry shall be substituted, namely :—

“2. Non-Government Railways—Matters in so far as provision for control by the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Railways Board (Rail Board) as provided in the Railways Act, 1989 (24 of 1989) or in the contracts between the Government and Railways, or in any other statutory enactments, namely, regulations in respect of safety, maximum and minimum rates and fares, etc. excluding the item of work allocated to the Department of Urban Development (Shahari Vikas Vibhag).”;

(B) under the heading “MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHAHRI VIKAS AUR GARIBI UPESHAMAN MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT (SHAHARI VIKAS VIBHAG)”,—

(i) for entry 13 the following entry shall be substituted, namely :—

“13 Planning and coordination of urban transport systems with technical planning of rail based systems being subject to the items of work allocated to the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Railway Board (Rail Board)”;

(ii) after the entry 13, so substituted, the following entry shall be inserted, namely :—

“13A Fixing of maximum and minimum rates and fares for rail-based urban transport systems other than those funded by the Indian Railways.”.

A.P.J. ABDUL KALAM
PRESIDENT

[F No. 1/22/1/2002-CAB.]

P. GOPALAKRISHNAN, Director (Cabinet)